आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 11.07.2023 से 15.07.2023)

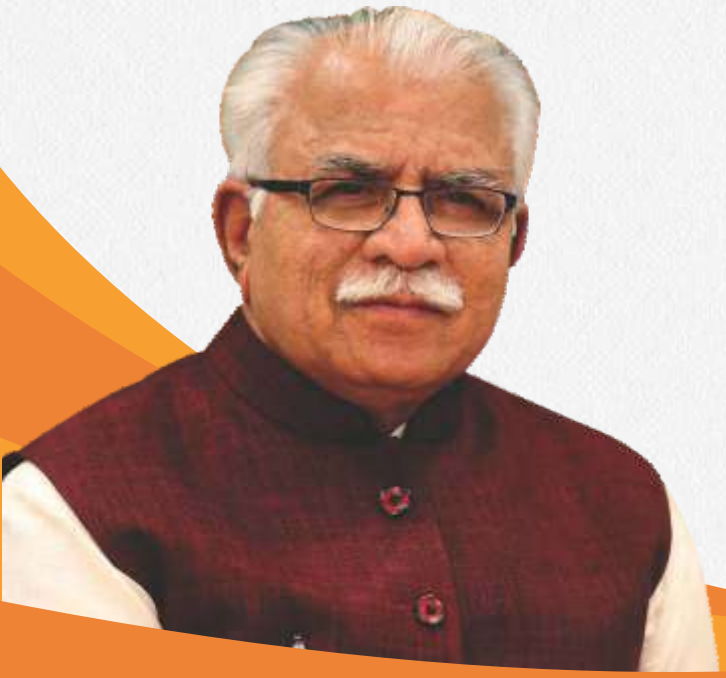

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरपंचों और पंचों के मानदेय में की बढ़ोतरी

(दिनांक 11.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5 हजार रुपए तथा पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगी। वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमशरू 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। सरपंचों व पंचों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया।

सरपंचों व पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु सरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम 1995 में संशोधन किया है। ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा की हमें अपनी पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर करने साथ ही मजबूत करने भी जरूरत है जिसके लिए हम निरंतर कदम उठा रहे है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

माननीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात

(दिनांक 11.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए जलभराव की वर्तमान स्थिति, पूरी हुई केन्द्रीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ हरियाणा में कुछ बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद हरियाणा भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए माननीय मुंख्यमंत्री जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रदेश में जलभराव तथा बाढ़ जैसी वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों के दौरान हरियाणा में बारिश अच्छी हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी ज्यादा

साप्ताहिक सूचना पत्र

बारिश होने के कारण भारी मात्रा में पानी हमारे यहां आया है। ज्यादा जलभराव वाले निचले स्थानों से लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना पडा है। रविवार और सोमवार को बरसात के कारण यमुना नदी का पानी तीन लाख 60 हजार क्यूसिक को छू गया था लेकिन आज यमुना का जल स्तर तीन लाख क्यूसिक से नीचे आ गया है।

एक सवाल के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अंबाला क्षेत्र में जलभराव इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि वहां पर दोनों तरफ से पानी की मार पड़ी। एक तरफ से एसवाईएल नहर में पानी आ गया तथा दूसरी तरफ से घग्गर व टांगरी नदियों में उफान से वहां जलभराव हुआ। इससे उस क्षेत्र के 12–13 गांवों पर प्रभाव पड़ा और उन गांवों के लगभग 25 से 30 हजार लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। उन्हें सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, बैंकेट हॉल आदि में रखा गया है और प्रशासन, एनडीआरएफ तथा सेना सभी मिलकर राहत व बचाव कार्यो में लगे हैं। इन लोगों के लिए भोजन, पानी तथा जरूरी वस्तुएं पहुंचाई जा रही है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पानीपत में भी एक स्थान पर नहर में कटाव हुआ था, जिसे कन्ट्रोल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पानी का फैलाव होने से नुकसान कम होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंचकूला में कुछ पुल टूटे है और मोरनी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। अब वर्षा रूकने के बाद सभी विभाग अपने –अपने तौर पर व्यवस्थाओं को ठीक करेगें और आने वाले 24 से 48 घण्टों में स्थिति सामान्य होने की आशा है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी हुई केन्द्रीय योजनाओं की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसमें विशेषकर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसे हरियाणा में लाल डोरा मुक्त योजना के तौर पर शुरू करवाया गया था और बाद में केन्द्र सरकार ने इसे अपनाकर पूरे देश में लागू किया है। उन्होंने बताया

साप्ताहिक सूचना पत्र

कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को पूरा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश के सभी 6500 गांवों में इस योजना को लागू कर पूरा किया गया है। इसी प्रकार ग्राम सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से भारत नैट परियोजना के अंर्तगत गांवों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने की परियोजना को भी हमने पूरा कर लिया है। इसके तहत सभी सार्वजनिक सेवाओं की जगहों, चाहे ग्राम सचिवालय हो या आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल, पीएचसी, सीएचसी आदि सभी संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़कर हमने हरियाणा में आईटी क्षेत्र में बड़ा काम पूरा कर लिया है।

उन्होंने कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी को न्यौता दिया है। इन परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि गुरूग्राम तथा नूंह जिलों में अरावली सफारी पार्क विकसित करने व रेवाड़ी में एम्स स्थापित करने की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है।

इनका शिलान्यास करने का निमंत्रण दिया है। इसी प्रकार अंबाला–कोटपुतली राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर–152डी, जो कि ग्रीन फील्ड मार्ग है, को हालांकि वाहन चालकों के लिए खोल दिया गया है लेकिन इसका विधिवत जनता को समर्पित करने के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अब कावड़ यात्रा का सीजन है। कावड़ यात्रियों के लिए प्रदेश में सभी व्यवस्थाएं की हुई है। फिर भी किसी को कठिनाई आती है तो जगह–जगह कैम्प लगे हुए हैं और टेलीफोन नंबर भी सार्वजनिक किये हुए हैं जिन पर वे सूचना दे सकते हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मासिक रैंकिंग में प्रथम सीन

(दिनांक 12.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) में प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मई माह 2023 की मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। विदित है की हरियाणा पुलिस फरवरी व मार्च माह में भी 2 माह लगातार रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंडो में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए प्रदेश पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रदेश पुलिस द्वारा प्राथमिकी पंजीकरण, गैर संज्ञेय रिपोर्ट, मेडिको लीगल केस, गुमशुदा व्यक्ति, खोयी हुई संपत्ति,लापता मवेशी, विदेशी पंजीकरण, सी–फार्म, लावारिस/परित्यक्त संपत्ति, अज्ञात/पाया व्यक्ति, निवारक कार्यवाही, पर्यवेक्षण रिपोर्ट/प्रगति का पंजीकरण,

अज्ञात मृत शरीर/अस्वाभाविक मृत्यु पंजीकरण, अनुसंधान संबंधी कार्य, शिकायतों के पंजीकरण, डेटाबैंक सेवाएं आदि कार्य किये जाते हैं। इस उपलब्धि पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ओ पी सिंह, आईपीएस और अन्य सभी राजपत्रित अधिकारियों व सीसीटीएनएस शाखा में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का रजत जयंती समारोह

(दिनांक 12.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1998 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिली है। इसकी स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन है। इंडियन ऑयल ने इस रिफाइनरी के लिए आने वाले वर्षों में 25 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर 35 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस विस्तार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रिफाइनरी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। विस्तार के लिए रिफाइनरी के आसपास के 3 गांवों पाल जाटान, खंडवा और आसन कलां की पंचायतों से बात हुई है और उन्होंने ऑफर किया है कि वे लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन इंडियन ऑयल को देने के लिए तैयार हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रबंधक मण्डल से आग्रह किया कि गत दिनों राज्य में हुई भारी बारिश के चलते जिन जिलों में नुकसान हुआ है, वहां राहत व बचाव कार्यों में अपना योगदान अवश्य दें। भारी बारिश के कारण 239 गांव प्रभावित हुए हैं, इन गांवों में सरकार हर स्तर पर राहत व बचाव का का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की प्रतिबद्धता के तहत इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पानीपत रिफाइनरी ने हरियाणा के 22 जिलों के लिए हैंड हेल्ड एक्स–रे मशीनें वितरित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी ने समाज के सभी वर्गों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए हैं। हाल ही में समालखा और पानीपत के सिविल अस्पतालों को सी.बी.नाट मशीनें प्रदान की गई हैं जिसके मरीजों को काफी लाभ हुआ है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आज के इस शुभ अवसर पर इंडियन ऑयल द्वारा हरियाणा के 22 जिलों में एक्सरे

साप्ताहिक सूचना पत्र

मशीनें उपलब्ध कराई है यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस अवसर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडियन ऑयल रिफाइनरी वनस्थली का उद्घाटन किया। रिफाइनरी द्वारा पानीपत की भूमि को हरा–भरा बनाने की दिशा में 12 एकड़ भूमि पर 40 हजार से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण के इन कामों से पूरे पर्यावरण के लिए बहुत फायदा होगा। इस पर लगभग 441 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा देशभर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 विरासत पर्यटन स्थलों पर शुरू की गई स्वच्छ आईकोनिक स्थल पहल के अंतर्गत इंडियन ऑयल द्वारा ब्रह्म सरोवर में एसआईपी – 3 कार्यकलाप का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी द्वारा पानीपत में 7,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित किया जा रहा है, इसके अलावा, रिफाइनरी की ओर से यहां दैनिक 1000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता का

साप्ताहिक सूचना पत्र

एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है।उन्होंने कहा कि हाल ही में इंडियन ऑयल ने बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की बहुत ही बढिया पहल की है। इस दिशा में पी.ई.टी. बोतलों की रीसाइक्लिंग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनबॉटल्ड जैकेट पहनी है। इस जैकेट की खासियत यह है कि इसे इंडियन ऑयल द्वारा पी.ई.टी. बोतलों की रीसाइक्लिंग से बनाया गया है। यह एक अनोखा प्रयास है। उन्होंने कहा कि पानीपत रिफाइनरी, भारत के सबसे बड़े तेल एवं गैस आधारित सार्वजनिक उपक्रम, इंडियन ऑयल की 11 रिफाइनरियों में प्रमुख है। इंडियन ऑयल ग्रुप देश में होने वाले तेल शोधन का लगभग एक तिहाई शोधन करता है। इसके पास पूरे देश में 34 हजार फ्यूल स्टेशन हैं। ये देश के ईंधन रिटेल मार्किटिंग बुनियादी ढांचे का लगभग आधा हिस्सा हैं। भारत के उद्योग क्षेत्र में तेल और गैस उद्योग देश को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसी दिशा में यह कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा राज्य सहित पूरे देश की विकास गाथा में पानीपत रिफाइनरी का अद्वितीय योगदान है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

अंबाला जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा

(दिनांक 12.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गत दिनों राज्य में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए लगभग 4–5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की।

जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जलभराव वाले इलाकों से पानी की निकासी के साथ–साथ लोगों के लिए खाने–पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा, खेतों से भी पानी की निकासी की जाए, क्योंकि यह बुआई का मौसम है, इसलिए किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मृतकों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि नाव के साथ साथ आज से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भी गांव गांव तक भोजन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब पानी धीरे–धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने–अपने जिलों में माली नुकसान का आकलन करें।

जिन गरीब परिवारों के घरों का नुकसान हुआ है, उन्हें तुरंत सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन फंड से भी सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी की निकासी के लिए यदि प्रशासन को और अधिक पंपों की आवश्यकता है तो वे तुरंत अपने स्तर पर व्यवस्था करें या मुख्यालय को सूचित करें।

पानी की निकासी के बाद इलाकों में सफाई व्यवस्था पर जरूर ध्यान दिया जाए। नागरिकों को किसी भी प्रकार

साप्ताहिक सूचना पत्र

की समस्या का सामना न करना पड़े यह जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी इलाकों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहां पाइपलाइन से जलापूर्ति अभी संभव नहीं है, उन इलाकों में पानी के टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करें। इस कार्य में समाजसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। साथ ही, सीवरेज की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुओं के चारे की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। जो जिले अपने स्तर पर पशुओं के चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों से भी चारे की व्यवस्था करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक बारिश से 240 गांवों के प्रभावित होने की सूचना है। इसलिए इन गांवों में बीमारियों के बढ़ने की भी संभावना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 से

3 दिनों के लिए विशेष कैंप लगाकर लोगों को दवाईयां उपलब्ध करवाएं।

बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि निचले इलाकों से पानी की निकासी जल्द से जल्द करें। पानी के टैंकरों की आपूर्ति के लिए भी एक सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि जरूरत के अनुसार टैंकर भेजे जा सकें। बिजली, पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था करने पर ध्यान दें।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भिवानी–महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात

(दिनांक 13.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भिवानी–महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर कहा कि राज्य सरकार उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की योजना तैयार कर रही है। इनके लिए किसान स्वयं ही भूमि देने को तैयार होगें तो जल्द ही ऐसी परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र में भूमि की पहचान कर सरकार को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि भिवानी, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे जिनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।

इनसे विशेषकर स्वरोजगार के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से एक हजार एकड़ भूमि की खरीद की गई है। इस पोर्टल पर किसानों ने यह जमीन ईच्छानुसार दी है जिसकी कमेटी द्वारा खरीद की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने साढे 8 साल के कार्यकाल में एक इंच भूमि को भी अधिग्रहण नहीं किया है।

केवल आवश्यक जमीन ही ली गई है जिस पर रेलवे लाईन, सडक़े आदि बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पदमा योजना के लिए ही 25 एकड़ तक भूमि देने के लिए किसान सहमत हैं। उन्होंने कहा कि पहले अधिग्रहण की हुई भूमि पर बार–बार इन्हासमेंट आती रही, जो सभी पर भारी पड़ती है। इसलिए सरकार किसानों की सहमति से ही विकास परियोजनाओं के लिए भूमि लेने के लिए कदम उठा रही है।

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को

साप्ताहिक सूचना पत्र

अवगत करवाया गया कि महेंद्रगढ़ के गांव मूसनौता, अटेली बेगपुर, बिहाली, खुडाना आदि कई गांवों में 100 से 200 एकड़ तक भूमि किसानों की सहमति से ली जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों से स्वेच्छा से भूमि देने बारे किसानों से बातचीत करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए सी एम विण्डों, विकास कार्यो के लिए जन संवाद पोर्टल तथा ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल बनाए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मंत्रियों ने जुलाई माह में संवाद कार्यक्रम किए हैं। उसी प्रकार जल्द ही सांसद भी जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जनसंवाद के लिए सांसदों को संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में कुछ गांव चयन कर दिये जाएगें। सांसद उन गांवों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि भिवानी–महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तोशाम, भिवानी, लोहारू, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, चरखी दादरी, बाढडा के जनप्रतिनिधियों की समस्याओं की सुनवाई के लिए अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की 9 कमेटियां बनाई गई। जनप्रतिनिधियों ने विस्तार से विकास कार्यो बारे अवगत करवाया।

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुग्राम के जी 20 दो दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन

(दिनांक 14.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज गुरुवार को गुरुग्राम के हयात रिजेंसी होटल परिसर में दो दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने सांस्कृतिक संध्या में मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों व सांस्कृतिक मंच के प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज जी20 के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित कर रहा है। विदेशी प्रतिनिधि सुखद माहौल में विषय विशेष से जुड़े सम्मेलन में भागीदार बनते हुए हरियाणा के आतिथ्य सत्कार के मुरीद बन गए हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश आमजन तक पहुंचाया जा रहा है, वह सराहनीय है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग व हरियाणा पुलिस की स्टॉल पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया है और दो दिन में विदेशी प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित लोग स्टॉल से जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज जी 20 की अध्यक्षता कर रहा है और हरियाणा में जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का जो अवसर राज्य सरकार को मिला है, उस दायित्व को हरियाणा सरकार बखूबी निभा रही है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

केंद्रीय कृषि मंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात

(दिनांक 14.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री जी से उनके आवास पर मुलाकात की और हरियाणा सरकार द्वारा किसान हित में लिए जा रहे निर्णयों से अवगत कराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं हेतु अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से बातचीत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में लागू की गई योजनाओं का लाभ हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को प्रभावी ढंग से

पहुंचा रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने किसान हित में हरियाणा सरकार की नीतियों को पूरे देश के लिए आदर्श बताते हुए उन्हें हर संभव सहयोग दिए जाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों व उनके लाभ के लिए सजग एवं सतर्क है, ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के किसान हित में उठाए जा रहे निर्णय में वे निरंतर सहयोगी रहेंगे।

बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य जिसमें मेरी फसल–मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसानों की कृषि योग्य बोई गई फसलों का संपूर्ण डाटा रिकार्ड किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी रूप से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में खेत की बुआई करने वाले किसान को प्रभावित हुई फसल का मुआवजा समय पर दिया जाए। बैठक में उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के समक्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित किसानों को आ रही तकनीकी

कठिनाईयों से भी अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किसानों की संतुष्टि हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के समक्ष वे विभिन्न सुझाव रखते हुए समाधान करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी रूप से किसानों को कोई असुविधा न हो इसके लिए हर स्तर पर सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि किसानों की बागवानी फसलों पर भी सरकार का पूरा फोकस है और हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से भी किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात

(दिनांक 14.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करने के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत कर कहा कि राज्य के पात्र लोगों को जल्द ही एक लाख आवास मुहैया करवाए जाएंगें। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत हमने कुछ लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए आज उन्होंने केंद्रीय शहरी एवं आवास मामले मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने पास किया जिसके लिए उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया है और आग्रह किया है कि इस परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट, जिनमें सराय कालेखां से पानीपत, सराय कालेखां से शहजादपुर की दोनों लाईनों पर कार्य शुरू करने के संबंध में भी चर्चा की गई है। परियोजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा अड़चने डाली जा रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है तथा इस मामले में आगामी 24 जुलाई की तारीख लगी हुई है। इसी प्रकार, आरआरटीएस के तहत आने वाली कठिनाई पर भी चर्चा की गई है। इन परियोजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सुझाव दिया गया है कि सराय कालेखां से शहजादपुर वाली लाइन को दिल्ली के न मानने पर ऐरो सिटी से उस लाइन को चालू किया जाए ताकि हरियाणा के भाग में लाईन चालू हो सके। इसी प्रकार, पानीपत की लाईन पर दिल्ली को भी 3000 करोड रुपये देना है, इस संबंध में भी विचार किया गया है।

एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 15.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में लगभग 620.88 करोड़ रुपये की खरीद व कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 15.47 करोड़ रुपये की बचत की गई है। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल, ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। हाई पावर परचेज कमेटी में सिंचाई, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के 10 एजेंडे और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में लोक निर्माण (भवन और सड़कें) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4 एजेंडे रखे गए और सभी एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई।

साप्ताहिक सूचना पत्र

बैठक में मंजूर किए गए कॉन्ट्रेक्ट व खरीद प्रक्रियाओं में जिला सिरसा में सिरसा–लुदेसर–भादर रोड का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिला गुरुग्राम में पंचगांव से जमालपुर होते हुए फर्रुखनगर तक दो लेन सड़क का निर्माण, अंबाला शहर में 100 बिस्तरों वाले तपेदिक और कार्डियोपल्मोनरी रोग राज्य संस्थान का निर्माण, हांसी टाउन, जिला हिसार में वाटरवर्क्स का नवीनीकरण और उन्नयन, पुराने वाटरवर्कस की मरम्मत और 8 एमएलडी जल उपचार संयंत्र का निर्माण, 20 केवीए व 10 केवीए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की खरीद, रोहतक क्षेत्र में आईएमटी खरखौदा से जुड़ी 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, आईएमटी खरखौदा (पॉकेट–ए) में 220 केवी सबस्टेशन व आईएमटी खरखौदा (पॉकेट–बी) सोनीपत में 220 केवी सबस्टेशन का निर्माण, तथा चिक्कनवास में 220 केवी सबस्टेशन का निर्माण कार्य शामिल है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक

(दिनांक 15.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज चण्डीगढ़ में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कहा कि प्रदेश की मंडियों में संचालित अटल किसान मजदूर कैंटीन को ऑफ सीजन भी खुला रखा जाएगा ताकि किसानों और मजदूरों को ऑफ सीजन भी मंडियों में खाना मिल सकें।

इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी.दलाल और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आदित्य देवी लाल भी उपस्थित रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन संचालित है जहां पर किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर पर भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

ऐसी ही 15 कैंटीन मंडियों में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5 जिलों की सड़के जो जिला परिषद को दी गई है उनकी निगरानी के लिए मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य अभियन्ता को

साप्ताहिक सूचना पत्र

नोडल अधिकारी लगाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों में क्या–क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसकी मैपिंग करवाकर जल्द ही वहां पर सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में सर्वे करवाया जाए कि कहां–कहां पर 5 करम के कच्चे रास्ते है उसकी रिपोर्ट जल्द दी जाए। उन्होंने कहा कि किसान एंव खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेती कार्यो के दौरान किसानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वितीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 में 1334 मामलों में 21.64 करोड़ रूपयें की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि एचएसएएमबी ने प्रदेश की 108 मंडियों को ई–एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, बैठक में सेब मंडी पिंजोर, मंडी बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्य व नए होने वाले कार्यों, मुख्यमंत्री घोषणा, नई भर्ती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ईस अवसर पर आज 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। इससे किसान घर बैठे अपनी पूरी फसल का पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा उसे 100 रुपये दिए जाऐंगे।

साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य के मिनी और हाई–टेक डेयरी मालिकों के साथ बातचीत

(दिनांक 15.07.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शिवरात्रि के अवसर पर आज यहां अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर से 'सीएम की विशेष चर्चा' कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के मिनी और हाई–टेक डेयरी मालिकों के साथ बातचीत कर प्रदेश के लोगों, विशेषकर पशुपालकों को विशेष बधाई दी और भगवान शिव से प्रार्थना की है कि उनके दुधारू पशुओं को तंदुरुस्त रखे ।

उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सांझा डेयरी की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। जहां पर भी पंचायती भूमि या सरकारी भूमि होगी वहां पर सहकारिता के माध्यम से डेयरियां खोली जाएंगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा को दुध उत्पादन का देश में तीसरा स्थान है। सरकार का प्रयास है कि इसे एक नम्बर पर लाया जाए यह पशुपालकों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि पशुपालन के व्यवसाय में महिलाओं का भी विशेष योगदान होता है। दूध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में गाय का विशेष योगदान है। जैविक खाद के साथ–साथ हम गौ–मूत्र व इसके अन्य उत्पादों से पशुपालन अपनी आय बढ़ा

सकते है। इससे गौ–संवर्धन को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों और युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाई–टेक और मिनी डेयरी योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना के तहत 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत दो या तीन दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा 20 या अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने पर ब्याज में छूट दी जाती है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 13,244 डेयरियां स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने डेयरी मालिकों से सीधा संवाद कायम करते हुए कहा कि आप न केवल हाईटेक एवं मिनी डेयरी इकाइयों के लाभार्थी हैं, बल्कि एक प्रगतिशील पशुपालक भी हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर युवाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि खेती के साथ–साथ दुधारू पशु पालने की हमारी प्राचीन परंपरा है।

पहले दुधारू पशुओं को केवल दूध की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही पाला जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है और समय के साथ जरूरतें भी बदल गई हैं।

इसलिए पशुपालन को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। संवाद के दौरान हाईटेक और मिनी डेयरी मालिकों ने किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और राज्य में पशुपालकों के कल्याण के लिए शुरू

की गई योजनाएं उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ताकि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में भी पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान और बढ़ सके।

पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना पशुपालन के लिए पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालने वाले पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं और इस कार्ड से किसी भी पशुपालक को बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये का ऋण मिलता है। हालांकि, इससे ऊपर के ऋण के लिए, गारंटी देनी होगी। उन्होंने कहा, बैंकों द्वारा अब तक 1.54 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और ऋण की किश्तें समय पर चुकाएं, ताकि उन्हें आगे ऋण लेने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने अमूल का उदाहरण देते हुए कहा कि आज अमूल दुग्ध के उत्पाद देश के हर हिस्से में उपलब्ध हैं। हरियाणा में वर्तमान में दूध की खरीद के लिए राज्य में 3300 सहकारी दुग्ध समितियां हैं। इसके अलावा राज्य में दूध प्रसंस्करण के लिए 6 दुग्ध संयंत्र हैं, जिनकी दैनिक दूध प्रसंस्करण क्षमता 9.45 लाख लीटर है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पशुपालन को जोखिम मुक्त बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक अपने बड़े पशु का बीमा दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार 100 से 300 रुपये और छोटे पशु का बीमा 25 रुपये का प्रीमियम देकर करा सकता है। योजना के तहत 8.52 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। उन्होंने किसानों से अपने पशुओं का बीमा कराने का आग्रह किया। इसी प्रकार दुर्घटना बीमा

साप्ताहिक सूचना पत्र

योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों का 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति बीमा किया जाता है। अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 62 लाभार्थियों को 3.10 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा अपनी मुर्राह नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने इस नस्ल के संरक्षण एवं विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा, मुर्राह भैंस की नस्ल में सुधार के लिए जिला हिसार के खांडा खेड़ी में एक क्षेत्रीय मुर्राह विकास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता और अधिक दूध देने वाली मुर्राह भैंस के मालिकों को 30,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमने सबसे गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान

योजना शुरू की है। इसके तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा 60 हजार 431 आवेदन बैंकों को प्रायोजित किए जा चुके हैं। इनमें से 20 हजार से अधिक आवेदकों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा चुका है। मैं इन परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। दूध की बिक्री के लिए भी हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ आपकी हर संभव सहायता करेगा। अगर फिर भी आपके समक्ष किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, तो आप टोल फ्री नम्बर–95001122261 पर सम्पर्क कर सकते हैं।